

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1125
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत शिक्षा के स्तर में गिरावट

1125. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के कभी स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या है;
- (ख) क्या देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे गिरने लगा है; और
- (ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और बच्चों को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया जा रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग "शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाईज+)" पोर्टल का रखरखाव कर रहा है। यूडाईज+ द्वारा कभी स्कूल नहीं गए बच्चों के बारे में कोई डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है। पीएलएफएस वर्ष 2023-2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 5-11 वर्ष की आयु के 3.06% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कारण देश में शिक्षा के स्तर में गिरावट नहीं आई है। एनईपी 2020 ने सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी सुधार पेश किए हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, समान अधिगम के अवसरों और आधुनिक शिक्षाशास्त्र की आवश्यकता को पहचानते हुए, नीति ने

शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी, दक्षता-आधारित और परिणाम-उन्मुख बनाने के लिए पुनर्गठित किया है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने एनईपी 2020 के तहत विभिन्न पहलों को लागू किया है। स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों के लिए समावेशी और न्यायसंगत कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और राष्ट्रीय बोध पठन एवं संख्याज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत); विद्या-प्रवेश-तीन महीने के प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-पद्धति पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या, ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर), परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का निष्पादन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) का उद्देश्य विद्यार्थियों के मूल्यांकन को रटने की प्रक्रिया से बदलकर योग्यता-आधारित मूल्यांकन करना है; निष्ठा (विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0 का उद्देश्य संरचित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना और शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

इन पहलों का प्रभाव नामांकन दरों में वृद्धि, ड्रॉपआउट स्तरों में कमी, बेहतर अवसंरचना और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन में स्पष्ट है। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राथमिक स्तर पर 93%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 89.7%, प्रारंभिक स्तर पर 91.7% और माध्यमिक स्तर पर 77.4% तक पहुँच गया है, जबकि प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर घटकर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% रह गई है। स्कूल अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें बिजली की पहुँच वर्ष 2013-14 में 53% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 91.8% हो गई है, इंटरनेट की उपलब्धता 7.3% से बढ़कर 53.9% और पुस्तकालय सुविधाएँ 76.4% से बढ़कर 89% हो गई हैं।

अवसंरचना विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल अधिगम और शिक्षा तक समान पहुँच पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एनईपी 2020 ने अधिगम मानकों को बढ़ाने और देश की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने, इसे अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।